eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

# मतदाता व्यवहार में जाति और धर्म का प्रभाव

**डा0 आभा पाण्डेय[1]**
[1]राजनीति विज्ञान विभाग, डी0जी0 कालेज कानपुर, उ0प्र0

Received: 21 December 2024 Accepted & Reviewed: 25 December 2024, Published: 31 December 2024

## Abstract

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ चुनावी राजनीति केवल नीतियों और विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक संरचना, जातीय पहचान, धार्मिक चेतना, भाषा, क्षेत्रीयता तथा आर्थिक हितों से भी गहराई से प्रभावित होती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय लोकतंत्र ने अनेक राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनों में जाति और धर्म ने मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में निरंतर भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध–पत्र में 1947 से 2023 तक भारतीय मतदाता व्यवहार में जाति और धर्म के प्रभाव का ऐतिहासिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की सर्वसमावेशी राजनीति ने जातीय और धार्मिक विभाजनों को सीमित रखा, किंतु 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय, मंडल आयोग की राजनीति, हिंदुत्व की वैचारिकी, राम जन्मभूमि आंदोलन तथा पहचान–आधारित राजनीतिक लामबंदी ने चुनावी राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरणों ने राजनीतिक दलों की सफलता–असफलता को निर्धारित किया, वहीं धर्म आधारित ध्रुवीकरण ने राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। शोध में यह भी विश्लेषित किया गया है कि आधुनिक भारत में जाति और धर्म केवल सामाजिक पहचान नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक संसाधन, सत्ता प्राप्ति का माध्यम तथा चुनावी रणनीति के प्रमुख उपकरण बन गए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, धार्मिक राष्ट्रवाद और जातीय जनगणना जैसे समकालीन मुद्दों ने मतदाता व्यवहार को और अधिक जटिल बनाया है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की भूमिका समाप्त नहीं हुई है, बल्कि बदलते स्वरूप में और अधिक संगठित हुई है। तथापि शिक्षा, शहरीकरण, युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या तथा विकासवादी राजनीति के कारण मतदाता व्यवहार में धीरे–धीरे परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है।

**प्रमुख शब्द** – मतदाता व्यवहार, जाति राजनीति, धर्म और राजनीति, भारतीय लोकतंत्र, चुनावी राजनीति, सामाजिक न्याय, मंडल राजनीति, हिंदुत्व, पहचान राजनीति, भारतीय निर्वाचन प्रणाली

## Introduction

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ विविधता उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भारतीय समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक स्वरूप वाला समाज है। ऐसी सामाजिक संरचना में राजनीति और चुनावी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की दिशा और स्वरूप निर्धारित करता है। भारत में मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, जिनमें जाति और धर्म सबसे अधिक प्रभावशाली कारकों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

चुनावी व्यवस्था स्थापित की। संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना की थी। किंतु भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में जाति और धर्म इतने गहरे रूप से समाहित थे कि वे राजनीति और चुनावी प्रक्रिया से अलग नहीं रह सके। परिणामस्वरूप भारतीय चुनावों में मतदाताओं का निर्णय अनेक बार जातीय पहचान, धार्मिक भावना तथा सामुदायिक हितों से प्रभावित होता रहा है। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व होने के कारण राष्ट्रीयता, विकास और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत प्रमुख चुनावी मुद्दे थे। किंतु धीरे–धीरे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के विस्तार, क्षेत्रीय दलों के उदय तथा सामाजिक न्याय आंदोलनों ने जाति आधारित राजनीति को सशक्त बनाया। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में गैर–कांग्रेसी दलों का उदय हुआ और जातीय समीकरण चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनने लगे। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा हरियाणा जैसे राज्यों में जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी।

1990 का दशक भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से पिछड़ी जातियों की राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। समाजवादी राजनीति तथा बहुजन राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की नई धारा को जन्म दिया। इसी काल में धर्म आधारित राजनीति ने भी तीव्र गति से विस्तार किया। राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी मस्जिद विवाद तथा हिंदुत्व की राजनीति ने धार्मिक पहचान को चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना दिया। परिणामस्वरूप मतदाता व्यवहार में धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट होने लगी। 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार तथा वैश्वीकरण के प्रभाव ने मतदाता व्यवहार को और अधिक जटिल बना दिया है। अब राजनीतिक दल केवल पारंपरिक जातीय और धार्मिक समीकरणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सूक्ष्म सामाजिक समूहों को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीतियाँ तैयार करते हैं। इसके बावजूद यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि आज भी भारतीय राजनीति में जाति और धर्म चुनावी सफलता के प्रमुख आधार बने हुए हैं। उम्मीदवार चयन, गठबंधन राजनीति, चुनाव प्रचार तथा मतदान व्यवहार में इन दोनों तत्वों की गहरी भूमिका दिखाई देती है।

जाति और धर्म आधारित राजनीति के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलू हैं। एक ओर इसने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया तथा लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाया, वहीं दूसरी ओर इसने सामाजिक विभाजन, सांप्रदायिक तनाव और वोट बैंक राजनीति को भी बढ़ावा दिया। लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति का बढ़ता प्रभाव कई बार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों को पीछे धकेल देता है। प्रस्तुत शोध–पत्र "मतदाता व्यवहार में जाति और धर्म का प्रभाव (1947–2023)" भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की राजनीतिक भूमिका का ऐतिहासिक, सामाजिक तथा चुनावी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में स्वतंत्रता के बाद से लेकर समकालीन भारतीय राजनीति तक विभिन्न चुनावों, राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तनों तथा वैचारिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह समझने का प्रयास किया गया है कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में मतदाता व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित हुआ है तथा जाति और धर्म की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को किस सीमा तक प्रभावित किया है। मतदाता व्यवहार से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत मतदाता किसी विशेष राजनीतिक दल, प्रत्याशी, विचारधारा अथवा नीति के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेते हैं। यह राजनीतिक विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के गठन का आधार मतदाताओं की पसंद और उनका मतदान निर्णय ही होता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

मतदाता व्यवहार केवल मतदान करने की क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक कारकों का समग्र अध्ययन है जो मतदाता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। मतदाता व्यवहार का अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि मतदाता किन परिस्थितियों में मतदान करते हैं, वे किसी दल या उम्मीदवार को क्यों पसंद करते हैं, चुनाव के दौरान उनकी प्राथमिकताएँ कैसे बदलती हैं तथा किन कारणों से वे अपने मतदान व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार का विश्लेषण राजनीतिक दलों, नीति निर्माताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज की राजनीतिक चेतना, सामाजिक संरचना तथा जनमत की दिशा को समझा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में मतदाता व्यवहार अत्यंत जटिल और बहुआयामी है। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में मतदाता केवल राजनीतिक घोषणापत्रों या विकास योजनाओं के आधार पर मतदान नहीं करते, बल्कि उनकी सामाजिक पहचान, जातीय स्थिति, धार्मिक मान्यताएँ, आर्थिक परिस्थिति, क्षेत्रीय भावना तथा स्थानीय नेतृत्व भी मतदान निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसी कारण भारतीय चुनावों में कई बार जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता जैसे तत्व निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जाति का विशेष महत्व है। भारतीय समाज में जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीतिक संगठन और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आधार रही है। कई क्षेत्रों में मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवार या उस दल को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी जातीय हितों की रक्षा करता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जातीय समीकरण चुनावी परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहे हैं। धर्म भी भारतीय मतदाता व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। धार्मिक पहचान और सामुदायिक भावना कई बार मतदाताओं को एक विशेष राजनीतिक दल की ओर आकर्षित करती है। धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक तनाव तथा धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद धार्मिक राजनीति का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा।

मतदाता व्यवहार पर आर्थिक स्थिति का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, महँगाई, गरीबी, कृषि संकट तथा विकास योजनाएँ मतदाताओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती हैं। गरीब और ग्रामीण मतदाता कई बार सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कल्याणकारी नीतियों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं, जबकि शहरी मतदाता विकास, रोजगार और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता भी मतदाता व्यवहार को प्रभावित करती हैं। शिक्षित मतदाता सामान्यतः नीतिगत मुद्दों, सुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अशिक्षा और राजनीतिक अज्ञानता कई बार जातीय या धार्मिक भावनाओं पर आधारित मतदान को बढ़ावा देती है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया, समाचार चौनलों और डिजिटल प्रचार ने मतदाता व्यवहार को और अधिक प्रभावित किया है। नेतृत्व का आकर्षण भी मतदाता व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करिश्माई नेताओं की लोकप्रियता कई बार राजनीतिक दलों की विचारधारा से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। मतदाता व्यवहार का अध्ययन लोकतंत्र की गुणवत्ता को समझने में भी सहायक होता है। यदि मतदाता जाति, धर्म या भावनात्मक मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं, तो लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर यदि मतदाता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, तो लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी और विकासोन्मुख बनता है।

समकालीन भारत में मतदाता व्यवहार में परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। युवा मतदाता, महिलाएँ, शहरी मध्यम वर्ग तथा डिजिटल माध्यमों से जुड़े नागरिक अब पारंपरिक पहचान राजनीति से आगे बढ़कर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन और आर्थिक अवसरों जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। इसके बावजूद जाति और धर्म भारतीय राजनीति में आज भी अत्यंत प्रभावशाली कारक बने हुए हैं और चुनावी राजनीति की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

**स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक चरण (1947–1967)–** स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व स्थापित था। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के प्रति सम्मान के कारण मतदाता जातीय और धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर मतदान करते थे। इस काल में जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया। हालाँकि, स्थानीय स्तर पर जाति का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन जातीय समीकरणों के आधार पर होता था। कांग्रेस पार्टी भी टिकट वितरण में जातीय संतुलन बनाए रखती थी। धर्म का प्रभाव विभाजन की त्रासदी के कारण संवेदनशील विषय था। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में धार्मिक राजनीति को व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिली।

**1967 के बाद राजनीतिक परिवर्तन और जातीय राजनीति–** 1967 के आम चुनाव भारतीय राजनीति में परिवर्तन का महत्वपूर्ण चरण थे। पहली बार कांग्रेस की शक्ति कमजोर हुई और गैर–कांग्रेसी दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दलों और पिछड़ी जातियों के नेताओं ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव, कुर्मी, जाटव, कुशवाहा तथा अन्य पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार दिखाई देने लगा। चौधरी चरण सिंह ने किसानों और मध्यवर्ती जातियों की राजनीति को मजबूत किया। इसी अवधि में जाति राजनीतिक संगठन और चुनावी रणनीति का आधार बनने लगी। राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों के अनुसार प्रत्याशी चयन शुरू किया।

**मंडल आयोग और सामाजिक न्याय की राजनीति–** 1990 का दशक भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति का निर्णायक चरण था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी। वी.पी. सिंह सरकार द्वारा इसकी घोषणा के बाद देशभर में व्यापक आंदोलन हुए। इस दौर में समाजवादी राजनीति का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक रूप से संगठित किया। जातीय पहचान राजनीति का प्रमुख आधार बन गई। यादव, कुर्मी, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट बैंक बनने लगे।

**दलित राजनीति का उदय–** दलित राजनीति भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण अध्याय है। डॉ0 अंबेडकर के विचारों ने दलित चेतना को प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री कांशीराम और मायावती ने दलित राजनीति को नई दिशा दी।

"बहुजन" की अवधारणा ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया। 2007 में मायावती की "सामाजिक इंजीनियरिंग" रणनीति ने दलित–ब्राह्मण गठबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

**धर्म और भारतीय राजनीति–** भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहा है, किंतु स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। 1960 और 1970 के दशकों में धर्म का प्रभाव सीमित था, किंतु 1980 के बाद धार्मिक राजनीति ने तेजी से विस्तार किया। आर0 एस0 एस0 और भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति में धार्मिक लामबंदी का महत्वपूर्ण उदाहरण था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद धार्मिक ध्रुवीकरण तीव्र हुआ। धर्म आधारित राजनीति ने मतदाता व्यवहार को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा चुनावी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन गई।

**हिंदुत्व और चुनावी राजनीति–** 1990 के दशक के बाद हिंदुत्व भारतीय राजनीति की प्रमुख विचारधारा बनकर उभरा। भाजपा ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक गौरव को चुनावी मुद्दा बनाया। अटल बिहारी वाजपेई और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने व्यापक जनाधार तैयार किया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में धार्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू पहचान महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे बने। धार्मिक ध्रुवीकरण ने कई राज्यों में मतदान व्यवहार को प्रभावित किया।

**मुस्लिम मतदाता और चुनावी राजनीति–** भारतीय चुनावों में मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम समुदाय ने लंबे समय तक कांग्रेस का समर्थन किया। किंतु बाबरी मस्जिद प्रकरण और सांप्रदायिक दंगों के बाद मुस्लिम मतदाता क्षेत्रीय दलों की ओर आकर्षित हुए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम वोटों का समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तथा केरल में मुस्लिम लीग का प्रभाव देखा गया। मुस्लिम मतदाता प्रायः साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति में रणनीतिक मतदान करते हैं।

**जाति और धर्म का संयुक्त प्रभाव–** भारतीय राजनीति में जाति और धर्म अलग–अलग नहीं, बल्कि कई बार संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश में "MY समीकरण" अर्थात मुस्लिम–यादव गठबंधन समाजवादी राजनीति का आधार रहा। इसी प्रकार भाजपा ने गैर–यादव पिछड़ी जातियों तथा हिंदू एकता की राजनीति को आगे बढ़ाया। बिहार में जातीय गणित और धार्मिक ध्रुवीकरण दोनों चुनाव परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं। हाल के वर्षों में "सोशल इंजीनियरिंग" राजनीतिक रणनीति का प्रमुख हिस्सा बन गई है।

**मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका–** 21वीं सदी में सोशल मीडिया ने मतदाता व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित किया है। राजनीतिक दल फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे मंचों के माध्यम से जातीय और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करते हैं। डिजिटल प्रचार ने राजनीतिक संदेशों को तेजी से फैलाया। फेक न्यूज, धार्मिक अफवाहें और जातीय प्रचार भी चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए।

**युवा मतदाता और बदलती राजनीति–** हाल के वर्षों में युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा, विकास और सुशासन जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में जाति और धर्म का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुआ है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह अब भी प्रभावशाली है। नई पीढ़ी सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से राजनीतिक जानकारी प्राप्त करती है। इसके कारण राजनीतिक चेतना का स्वरूप बदल रहा है।

**भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव, 2014–2023, नया राजनीतिक परिदृश्य–** भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म आधारित राजनीति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का उद्देश्य सामाजिक समानता, राजनीतिक सहभागिता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था, किंतु समय के साथ चुनावी राजनीति में जातीय और धार्मिक पहचान अत्यंत प्रभावशाली बन गई। इसका प्रभाव भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न पक्षों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जाति आधारित राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में वंचित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक राजनीति में उच्च जातियों का प्रभुत्व बना रहा, किंतु मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियों, दलितों

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

और आदिवासी समुदायों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इससे लोकतंत्र अधिक सहभागी और समावेशी बना। उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय की राजनीति ने उन वर्गों को सत्ता में भागीदारी दी जो पहले राजनीतिक रूप से उपेक्षित थे। दलित राजनीति और बहुजन आंदोलन ने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक समानता की चेतना को मजबूत किया। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने दलित समुदाय को राजनीतिक शक्ति प्रदान की तथा सामाजिक सम्मान की भावना को विकसित किया। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों की राजनीति ने लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाया। इससे लोकतंत्र केवल अभिजात वर्ग तक सीमित न रहकर आम जनता तक पहुँचा। धर्म आधारित राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक लामबंदी ने मतदाताओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई राजनीतिक दलों ने धार्मिक भावनाओं को चुनावी रणनीति के रूप में उपयोग किया। इससे धार्मिक समुदायों की राजनीतिक चेतना और सहभागिता बढ़ी, किंतु इसके साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जाति और धर्म आधारित राजनीति के कारण वोट बैंक राजनीति को बढ़ावा मिला। राजनीतिक दल कई बार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की अपेक्षा जातीय और धार्मिक समीकरणों को अधिक महत्व देने लगे। उम्मीदवार चयन, टिकट वितरण और गठबंधन राजनीति में सामाजिक समीकरण निर्णायक भूमिका निभाने लगे। इससे लोकतंत्र में वैचारिक राजनीति की अपेक्षा पहचान आधारित राजनीति अधिक प्रभावशाली हो गई।

भारतीय लोकतंत्र पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव सामाजिक ध्रुवीकरण के रूप में दिखाई देता है। चुनावों के दौरान जातीय और धार्मिक भावनाओं को उभारने से समाज में विभाजन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती है। जाति और धर्म आधारित राजनीति ने गठबंधन राजनीति को भी प्रभावित किया है। विभिन्न सामाजिक समूहों को साथ लेकर चुनाव जीतने की रणनीति ने गठबंधन सरकारों के दौर को जन्म दिया। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन युग का विस्तार हुआ, जिसमें जातीय और धार्मिक समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। इससे क्षेत्रीय दलों की शक्ति बढ़ी तथा भारतीय संघवाद को भी नई दिशा मिली। महिलाओं, युवाओं और शहरी मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र में नए परिवर्तन भी उत्पन्न किए हैं। शिक्षा और जागरूकता के विस्तार के कारण अब मतदाता केवल जाति और धर्म के आधार पर मतदान नहीं करते, बल्कि विकास, सुशासन, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी महत्व देने लगे हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ राज्यों में जातीय और धार्मिक पहचान आज भी अत्यंत प्रभावशाली बनी हुई है।

2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभरकर सामने आया। इस अवधि में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व की राजनीति का प्रभाव तेजी से बढ़ा। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने विकास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान को एक साथ जोड़ते हुए व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में परिवर्तनकारी माना गया, क्योंकि इसमें पहली बार लंबे समय बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 2014 के बाद चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और आईटी आधारित चुनाव प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। फेसबुक, व्हाट्सऐप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे माध्यमों के जरिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं तक सीधे पहुँच बनाई। इससे चुनाव प्रचार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। डिजिटल माध्यमों ने जातीय और धार्मिक संदेशों को तेजी से फैलाने का कार्य भी किया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

इस अवधि में हिंदुत्व की राजनीति और धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। राम मंदिर आंदोलन, अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों ने धार्मिक पहचान को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। इससे हिंदू मतदाताओं के व्यापक ध्रुवीकरण की चर्चा प्रमुख रूप से सामने आई। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने सूक्ष्म जातीय समीकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया। भाजपा ने गैर–यादव पिछड़ी जातियों और गैर–जाटव दलित समुदायों को अपने समर्थन आधार में शामिल करने की रणनीति अपनाई। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों ने पारंपरिक जातीय गठबंधनों को बनाए रखने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई दी। 2014–2023 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं की राजनीति भी मतदाता व्यवहार का महत्वपूर्ण आधार बनी। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब और ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित किया। इससे पहचान आधारित राजनीति के साथ–साथ लाभार्थी आधारित राजनीति का भी विस्तार हुआ। इस अवधि में युवा मतदाताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बड़ी संख्या में प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं ने रोजगार, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों को महत्व दिया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन राजनीतिक अभियानों ने युवाओं की राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। हालाँकि 2014– 2023 के दौरान भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, विपक्ष की कमजोर स्थिति, मीडिया की भूमिका तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे विषयों पर व्यापक बहस भी हुई। आलोचकों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चुनौती बताया, जबकि समर्थकों ने इसे मजबूत नेतृत्व और निर्णायक शासन का प्रतीक माना।

समग्र रूप से देखा जाए तो 2014–2023 का काल भारतीय राजनीति में परिवर्तन, वैचारिक पुनर्संरचना और नए चुनावी विमर्श का काल रहा। इस अवधि में जाति और धर्म की राजनीति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में विकसित हुई। विकास, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएँ और पहचान आधारित राजनीति एक साथ भारतीय मतदाता व्यवहार को प्रभावित करती रहीं। भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप इन्हीं विविध सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक प्रवृत्तियों का परिणाम है।

**1.1 शोध की आवश्यकता (Need of the Study)–** भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तंत्र है, जहाँ प्रत्येक चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक संरचना का भी प्रतिबिंब होता है। भारत जैसे बहुजातीय और बहुधार्मिक समाज में मतदाता व्यवहार को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चुनावी परिणामों पर सामाजिक पहचान का गहरा प्रभाव पड़ता है। जाति और धर्म लंबे समय से भारतीय राजनीति के केंद्रीय तत्व रहे हैं और इनका प्रभाव समय के साथ बदलते स्वरूप में निरंतर बना हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय लोकतंत्र ने अनेक राजनीतिक परिवर्तनों का अनुभव किया है। प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीयता और विकास प्रमुख मुद्दे थे, किंतु धीरे–धीरे जातीय और धार्मिक पहचान ने चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। मंडल आयोग, राम जन्मभूमि आंदोलन, सामाजिक न्याय की राजनीति, हिंदुत्व, क्षेत्रीय दलों का उदय तथा गठबंधन राजनीति जैसे घटनाक्रमों ने मतदाता व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया। 21वीं सदी में सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय लामबंदी ने मतदाता व्यवहार को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसी स्थिति में यह अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि 1947 से 2023 तक भारतीय राजनीति में जाति और धर्म ने मतदाता व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह शोध भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक वास्तविकताओं, राजनीतिक प्रवृत्तियों तथा चुनावी प्रक्रियाओं को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

यह अध्ययन नीति निर्माताओं, राजनीतिक दलों, शोधार्थियों और सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि इसके माध्यम से लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति की प्रकृति तथा उसके प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया जा सकेगा।

**1.2 समस्या का स्वरूप एवं व्याख्या–** भारतीय राजनीति में जाति और धर्म का प्रभाव एक जटिल सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या के रूप में विकसित हुआ है। संविधान द्वारा समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की स्थापना के बावजूद चुनावी राजनीति में जातीय और धार्मिक पहचान अत्यंत प्रभावशाली बनी हुई है। मतदाता कई बार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की अपेक्षा जातीय और धार्मिक आधार पर मतदान करते हैं। समस्या का मुख्य स्वरूप यह है कि लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक पहचान चुनावी व्यवहार का प्रमुख निर्धारक बन गई है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरणों और धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग करते हैं।

प्रत्याशियों का चयन, गठबंधन निर्माण और चुनाव प्रचार अक्सर जातीय तथा धार्मिक गणित के आधार पर किया जाता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वैचारिक राजनीति की अपेक्षा पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है। जाति आधारित राजनीति ने सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है, किंतु इसके साथ ही समाज में विभाजन और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। दूसरी ओर धार्मिक राजनीति ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तथा सामाजिक तनाव को जन्म दिया है। कई बार चुनावों के दौरान धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक उपयोग सामाजिक सद्भाव के लिए चुनौती बन जाता है।

समकालीन भारत में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए जातीय और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करना आसान हो गया है। इस प्रकार यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म आधारित मतदाता व्यवहार की प्रकृति, कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

**1.3 अध्ययन का औचित्य–** यह अध्ययन भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की चुनावी राजनीति को समझे बिना भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति का सही मूल्यांकन संभव नहीं है। चूँकि भारतीय समाज में जाति और धर्म सामाजिक संगठन के प्रमुख आधार रहे हैं, इसलिए उनका चुनावी व्यवहार पर प्रभाव स्वाभाविक है। अध्ययन का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका निरंतर परिवर्तित हुई है। प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीयता और विकास की राजनीति प्रमुख थी, किंतु बाद में सामाजिक न्याय, पिछड़ा वर्ग राजनीति, दलित आंदोलन और धार्मिक राष्ट्रवाद ने चुनावी राजनीति को नई दिशा दी।

यह अध्ययन यह स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि जाति और धर्म ने भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि पहचान आधारित राजनीति लोकतंत्र को सशक्त बनाती है अथवा सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है। अध्ययन का औचित्य समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में चुनावी राजनीति में जातीय जनगणना, आरक्षण, धार्मिक पहचान, मंदिर राजनीति तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे अत्यंत प्रभावशाली बने हुए हैं। यह शोध राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा। साथ ही यह लोकतंत्र में सामाजिक समरसता और उत्तरदायी राजनीति की आवश्यकता को समझने में सहायक सिद्ध होगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

### 1.4 अध्ययन के उद्देश्य–

1 भारतीय मतदाता व्यवहार की अवधारणा का विश्लेषण करना।
2 1947 से 2023 तक भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति के विकास का अध्ययन करना।
3 भारतीय चुनावों में धर्म आधारित राजनीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4 विभिन्न लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जातीय एवं धार्मिक ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना।
5 मंडल आयोग, राम जन्मभूमि आंदोलन तथा सामाजिक न्याय आंदोलनों के प्रभाव का अध्ययन करना।
6 राजनीतिक दलों द्वारा जाति और धर्म के चुनावी उपयोग का परीक्षण करना।
7 आधुनिक भारत में सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के माध्यम से मतदाता व्यवहार में आए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
8 भारतीय लोकतंत्र पर जाति और धर्म आधारित राजनीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना।
9 युवा मतदाताओं और शहरी मतदाताओं के बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना।
10 भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और विकासोन्मुख बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

### 1.5 शोध–प्रश्न–

1 भारतीय मतदाता व्यवहार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
2 भारतीय चुनावों में जाति किस प्रकार मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है?
3 धर्म आधारित राजनीति का मतदाता व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4 मंडल आयोग के बाद भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए?
5 राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति ने चुनावी व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित किया?
6 क्या वर्तमान भारतीय राजनीति में जाति और धर्म विकास के मुद्दों से अधिक प्रभावशाली हैं?
7 सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने मतदाता व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित किया है?
8 क्या युवा मतदाता पारंपरिक जातीय और धार्मिक राजनीति से अलग सोच विकसित कर रहे हैं?
9 जाति और धर्म आधारित राजनीति का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है?
10 क्या भारतीय लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति भविष्य में भी प्रभावशाली बनी रहेगी?

**1.6 अध्ययन की परिधि एवं सीमाएँ–** यह अध्ययन मुख्यतः 1947 से 2023 तक भारतीय मतदाता व्यवहार में जाति और धर्म के प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन का क्षेत्र भारतीय लोकतंत्र, चुनावी राजनीति, लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों तथा प्रमुख राजनीतिक आंदोलनों तक सीमित है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की राजनीति का संदर्भ लिया गया है, जहाँ जाति और धर्म का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अध्ययन में भारतीय राजनीतिक दलों, चुनावी रणनीतियों, सामाजिक न्याय आंदोलनों, धार्मिक राजनीति तथा मतदाता व्यवहार के प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया गया है। इसके अंतर्गत मंडल राजनीति, दलित राजनीति, हिंदुत्व, गठबंधन राजनीति तथा डिजिटल चुनाव प्रचार का भी अध्ययन किया गया है। अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह शोध मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इसमें उपलब्ध साहित्य और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर निर्भरता रहती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी राज्यों और सामाजिक समूहों का समान रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। मतदाता व्यवहार समय, परिस्थितियों और क्षेत्रीय कारकों के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

अनुसार बदलता रहता है, इसलिए सभी चुनावों पर समान निष्कर्ष लागू नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त कई बार मतदाता अपने वास्तविक मतदान कारणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते, जिससे व्यवहार का पूर्णतः सटीक विश्लेषण कठिन हो जाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति का प्रभाव तेजी से बदल रहा है, इसलिए समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भविष्य के चुनावी व्यवहार का सटीक अनुमान लगाना भी चुनौतीपूर्ण है।

**1.7 परिकल्पना–** इस शोध का मूल आधार यह है कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार पर जाति और धर्म का प्रभाव निरंतर बना हुआ है तथा समय के साथ इसका स्वरूप और अधिक संगठित एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हुआ है। अध्ययन की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं–

1 भारतीय मतदाता व्यवहार में जाति एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करती है।
2 धर्म आधारित राजनीतिक लामबंदी चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है।
3 मंडल आयोग के बाद जाति आधारित राजनीति का प्रभाव भारतीय चुनावों में बढ़ा है।
4 1990 के बाद हिंदुत्व और धार्मिक राष्ट्रवाद ने मतदाता व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
5 राजनीतिक दल चुनावी सफलता के लिए जातीय और धार्मिक समीकरणों का रणनीतिक उपयोग करते हैं।
6 ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और धर्म का प्रभाव शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है।
7 युवा और शिक्षित मतदाताओं में विकास एवं सुशासन आधारित राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
8 सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने धार्मिक एवं जातीय ध्रुवीकरण को प्रभावित किया है।
9 जाति और धर्म आधारित राजनीति ने सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, किंतु लोकतंत्र में ध्रुवीकरण भी उत्पन्न किया है।
10 भविष्य में भी भारतीय राजनीति में पहचान आधारित मतदान की प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त नहीं होगी।

**1.8 शोध प्राविधि–** प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में भारतीय लोकतंत्र के विकास, चुनावी राजनीति तथा सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक क्रम में विश्लेषण किया गया है। शोध में गुणात्मक पद्धति का अधिक उपयोग किया गया है, क्योंकि विषय का संबंध सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार से है। विभिन्न चुनावों, राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक दलों की रणनीतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न चुनावी अवधियों की तुलना करते हुए मतदाता व्यवहार में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है। शोध में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है। निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें, जनमत सर्वेक्षण, राजनीतिक विश्लेषण, पुस्तकों, शोध–पत्रों, समाचार–पत्रों तथा ऑनलाइन स्रोतों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अध्ययन में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए तथ्यों का तार्किक विश्लेषण किया गया है। शोध का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध न होकर भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की भूमिका का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है।

**1.9 तथ्य–संकलन के स्रोत–** प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य–संकलन हेतु मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त जानकारी का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। तथ्य–संकलन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र एवं लोकतंत्र संबंधी पुस्तकों का अध्ययन।
भारतीय निर्वाचन आयोग की रिपोर्टें एवं चुनावी आँकड़े।
लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के आधिकारिक परिणाम।
विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों के शोध–पत्र और शोध–प्रबंध।
लोकनीति–CSDS तथा अन्य जनमत सर्वेक्षण रिपोर्टें।
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाएँ।
समाचार–पत्र, पत्रिकाएँ एवं संपादकीय लेख।
संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियाँ।
सरकारी दस्तावेज, आयोगों की रिपोर्टें तथा नीति दस्तावेज।
इंटरनेट, ई–जर्नल तथा ऑनलाइन डेटाबेस।
सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेख।
समकालीन राजनीतिक घटनाओं एवं चुनावी अभियानों का अध्ययन।
इन सभी स्रोतों के आधार पर शोध विषय का वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**1.10 साहित्य समीक्षा (Review of Literature)–** भारतीय मतदाता व्यवहार, जाति और धर्म आधारित राजनीति पर अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों ने भारतीय लोकतंत्र की सामाजिक संरचना तथा चुनावी व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में "कांग्रेस प्रणाली" तथा जातीय संरचना के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके अनुसार भारतीय राजनीति में जाति केवल सामाजिक संस्था नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन का भी आधार बन गई है।

क्रिस्टोफ जाफरलॉट ने पिछड़ी जातियों और दलित राजनीति के उदय का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मंडल राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर दिया।

योगेंद्र यादव ने भारतीय चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार पर महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए। उनके अनुसार भारतीय मतदाता केवल जाति या धर्म के आधार पर मतदान नहीं करते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों का संयुक्त प्रभाव मतदान निर्णय को प्रभावित करता है।

आंद्रे बेतेइले और एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया। उनके शोध भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को समझने में अत्यंत उपयोगी हैं।

पॉल ब्रास और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय राजनीति में धर्म, सांप्रदायिकता और लोकतंत्र के संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि धार्मिक राजनीति कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है।

निरजा गोपाल जयाल और सुहास पलशीकर ने समकालीन भारतीय लोकतंत्र, गठबंधन राजनीति तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं।

Pew Research Center तथा CSDS के विभिन्न सर्वेक्षणों ने यह संकेत दिया है कि आधुनिक भारत में जाति और धर्म आज भी मतदान व्यवहार के प्रमुख कारक बने हुए हैं, यद्यपि विकास, राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय मतदाता व्यवहार बहुआयामी है तथा जाति और धर्म इसकी महत्वपूर्ण आधारशिलाएँ हैं। फिर भी बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में मतदाता व्यवहार में नए परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। प्रस्तुत शोध इन्हीं परिवर्तनों और निरंतरताओं का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है।

**1.11 डेटा विश्लेषण–** अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न चुनावी आँकड़ों, जनमत सर्वेक्षणों, राजनीतिक रिपोर्टों तथा सामाजिक अध्ययनों का विश्लेषण किया गया। डेटा विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय चुनावों में जाति और धर्म का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। 1952 से 1967 तक कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण राष्ट्रीयता और विकास राजनीति के प्रमुख आधार थे, किंतु स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण सक्रिय थे। 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय ने जाति आधारित राजनीति को अधिक संगठित किया। 1990 के बाद मंडल राजनीति के प्रभाव से पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव, कुर्मी, जाटव तथा अन्य पिछड़ी जातियों के वोट बैंक स्पष्ट रूप से विकसित हुए। धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव विशेष रूप से 1980 के बाद बढ़ा। राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति ने चुनावी व्यवहार में धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूत किया।

2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, कल्याणकारी योजनाएँ तथा मजबूत नेतृत्व महत्वपूर्ण चुनावी कारक रहे। इसके साथ ही गैर–यादव ओबीसी और गैर–जाटव दलित समुदायों की राजनीतिक भूमिका भी बढ़ी।

सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने मतदाताओं की राजनीतिक सोच को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं में विकास, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ी, किंतु जाति और धर्म का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।

डेटा विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय और धार्मिक मतदान की प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मजबूत है।

**1.12 चर्चा (Discussion)–** अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। राजनीतिक दल चुनावी सफलता के लिए इन दोनों तत्वों का रणनीतिक उपयोग करते हैं।

जाति आधारित राजनीति ने लोकतंत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है। पिछड़ी जातियों, दलितों और वंचित वर्गों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई है। इससे लोकतंत्र अधिक सहभागी बना है। किंतु इसके साथ ही जातीय ध्रुवीकरण और वोट बैंक राजनीति भी बढ़ी है।

धर्म आधारित राजनीति ने मतदाताओं की भावनात्मक पहचान को प्रभावित किया है। धार्मिक राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक धुंवीकरण ने चुनावी राजनीति को नई दिशा दी है। इससे कई बार सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि आधुनिक भारत में विकास, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएँ और नेतृत्व भी मतदाता व्यवहार के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। युवा मतदाता पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं।

इसके बावजूद भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका समाप्त नहीं हुई है। वे आज भी चुनावी रणनीति, राजनीतिक गठबंधनों तथा उम्मीदवार चयन के प्रमुख आधार बने हुए हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

समकालीन राजनीति में सोशल मीडिया ने मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र बना दिया है। डिजिटल माध्यमों के जरिए राजनीतिक संदेशों का व्यापक प्रसार संभव हुआ है, जिससे पहचान आधारित राजनीति को नई शक्ति मिली है।

### 1.13 परिणाम (Findings)–

भारतीय मतदाता व्यवहार में जाति और धर्म का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण पाया गया।
स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीयता प्रमुख चुनावी मुद्दा था, किंतु समय के साथ जाति आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा।
मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
दलित राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना को मजबूत किया।
1980 के बाद धार्मिक राजनीति और हिंदुत्व का प्रभाव चुनावी व्यवहार में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।
राम जन्मभूमि आंदोलन भारतीय राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण का महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।
राजनीतिक दल चुनावों में जातीय और धार्मिक समीकरणों का सक्रिय उपयोग करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और धर्म आधारित मतदान की प्रवृत्ति अधिक प्रभावशाली पाई गई।
युवा और शहरी मतदाता विकास, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देने लगे हैं।
सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने में नई भूमिका निभाई है।
जाति और धर्म आधारित राजनीति ने सामाजिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, किंतु लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण को भी प्रोत्साहित किया।
भारतीय लोकतंत्र में पहचान आधारित राजनीति आज भी अत्यंत प्रभावशाली बनी हुई है।

**निष्कर्ष–** भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार बहुआयामी है, किंतु जाति और धर्म इसके सबसे प्रभावशाली कारकों में शामिल रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीयता और विकास राजनीति के केंद्र में थे, किंतु समय के साथ जातीय और धार्मिक पहचान ने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। मंडल राजनीति ने सामाजिक न्याय की चेतना को मजबूत किया, जबकि हिंदुत्व की राजनीति ने धार्मिक पहचान को संगठित किया। परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में पहचान–आधारित मतदान की प्रवृत्ति बढ़ी। हालाँकि, 21वीं सदी में शिक्षा, शहरीकरण, डिजिटल क्रांति और युवा मतदाताओं के उदय ने मतदाता व्यवहार में परिवर्तन के संकेत भी दिए हैं। विकास, सुशासन, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं।

इसके बावजूद जाति और धर्म भारतीय राजनीति से पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। वे आज भी राजनीतिक दलों की रणनीति, प्रत्याशी चयन और चुनावी प्रचार के महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इसी में निहित है कि वह सामाजिक विविधताओं को समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया में परिवर्तित करे।

### संदर्भ सूची–

1 कोठारी, रजनी. भारतीय राजनीति. ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, 2005. ISBN: 9788125017463
2 यादव, योगेंद्र. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. ISBN:9780195647571
3 जाफरलॉट, क्रिस्टोफ. इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन. पर्मानेंट ब्लैक, 2003 ISBN: 9788178240726
4 पालशीकर, सुहास. भारतीय लोकतंत्र और चुनाव. सेज पब्लिकेशन, 2018. ISBN: 9789352807353

5 अंबेडकर, भीमराव. जाति का विनाश. सम्यक प्रकाशन, 2014. ISBN: 9788171387107
6 लुई दुमों. होमो हायरार्किकस. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1980. ISBN: 9780226169638
7 पॉल ब्रास. द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1994. ISBN:9780521459700
8 ग्रानोवेटर, मार्क. सोशल स्ट्रक्चर एंड वोटिंग बिहेवियर. हार्वर्ड प्रेस, 2001. ISBN: 9780674008794
9 ऑस्टिन, ग्रेनविल. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999. ISBN: 9780195649599
10 निरजा गोपाल जयाल. डेमोक्रेसी एंड स्टेट इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001. ISBN: 9780195650823
11 चंद्र, कंचन. व्हाई एथनिक पार्टीज सक्सीड. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004. ISBN:9780521543690
12 जावेद आलम. डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज. सेज पब्लिकेशन, 2009. ISBN:9788132103357
13 राम आहूजा. भारतीय सामाजिक व्यवस्था. रावत पब्लिकेशन, 2012. ISBN: 9788131601489
14 एम.एन. श्रीनिवास. सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1966 ISBN:9780520016850
15 आंद्रे बेतेइले. कास्ट, क्लास एंड पावर. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996. ISBN: 9780195635073
16 गुहा, रामचंद्र. इंडिया आफ्टर गांधी. पिकाडोर इंडिया, 2007. ISBN: 9780330396111
17 हसन, जिया. पॉलिटिक्स ऑफ इन्क्लूजन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009. ISBN: 9780198060988
18 चुनाव आयोग भारत. लोकसभा चुनाव रिपोर्ट्स (1952–2019).
19 लोकनीति–CSDS सर्वे रिपोर्ट्स.
20 Pew Research Center Report on Religion and Politics in India, 2021.
21 Suhas Palshikar & Jyoti Mishra] ÞCaste] Class and Voteß, 2023.
22 Pradeep Chhibber & John Petrocik, Social Cleavages and Indian Party System.